

मनमोहन सिंह : एक सफल प्रधानमंत्री

कहा जाता है कि मनमोहन सिंह के अंदर राजनीति की समझ नहीं है। मेरी समझ में कोई गैर राजनीतिक व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाए तो, यह कोई बुराई नहीं है। मनमोहन सिंह अन्य राजनेताओं की तरह कलाकारी नहीं करते, नाटकबाज नहीं है। गरीब के बच्चे को गोद में उठाकर उसके प्रति करुणा का नाटक करना, अलग-अलग प्रदेशों में जाकर उन प्रादेशिक भाषाओं में दो-चार शब्द बोलकर लोगों का मन जीत लेना, शब्दाडम्बर युक्त भाषण देकर भीड़ को मोहित कर लेना अथवा प्रत्यक्ष छूट देकर परोक्ष रूप से ले लेना, यदि राजनीति का गुण है और मनमोहन सिंह ऐसा नहीं कर पाते, तो मैं मनमोहन सिंह का प्रशंसक हूँ। ऐसा व्यक्ति असफल सिद्ध किया जा सकता है किन्तु वास्तव में असफल होता नहीं।

मनमोहन सिंह सफल अर्थशास्त्री रहें हैं, अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए उनके मुकाबले में भारत में तो कोई अन्य सफल नहीं हो सका। 2009 के बाद अर्थव्यवस्था को राजनीति की कलाबाजियों ने असफल किया। मनमोहन सिंह ने भरसक कोशिश की कि अर्थव्यवस्था पटरी से ना उतरे किन्तु जब उन्हें महसूस हुआ कि अर्थव्यवस्था पटरी से उतर नहीं रही है, बल्कि जानबूझकर सोनिया जी द्वारा उतारी जा रही है, तब उन्होंने हथियार डाल दिया। 2009 तक सोनिया जी की नीयत अर्थव्यवस्था के मामले में ठीक-ठाक थी। 2009 के बाद ही उनकी नीयत में खोट आया। चाहे कोई भगवान भी अर्थशास्त्री बनकर आ जाए, तो यह कैसे संभव है कि खर्चा बढ़ता चला जाए और आमदानी घटती जाए। यह कैसे संभव है कि बजट घाटा बढ़ते जाए, नये-नये नोट छपते जाएं और मुद्रास्फीति ना बढ़े। यदि इतनी सामान्य सी बात भी हमारे मित्रों या पाठकों को समझ ना आवे तो मैं क्या करूँ ? 2007 में जब नरेगा चालू हुआ था, तो नरेगा की न्यूनतम मजदूरी 60 रुपये घोषित थी। 60 रुपये में भी बेरोजगारों की संख्या बहुत बढ़ी थी और बड़ी मुश्किल से कुछ परिवारों के एक सदस्य को सौ दिन के रोजगार की गारंटी थी। आज सात वर्षों में ही विभिन्न दबावों के अंतर्गत नरेगा की मजदूरी को बढ़ाकर नरेगा की मजदूरी को ढाई से तीन गुणा कर दिया गया, और वह भी वर्ष भर के लिए करा दिया गया। क्या बिगड़ जाता यदि मनमोहन सिंह पर इतना दबाव डालने की अपेक्षा स्वाभाविक गति से बढ़ने दिया जाता और बजट घाटा इतना नहीं बढ़ता। संभव है कि नरेगा की मजदूरी जो आज है, इससे दस या पंद्रह प्रतिशत कम बढ़ी होती। मनमोहन सिंह ने कई बार प्रयास किया, सोनिया जी को भी समझाया और देश को भी बताया कि ऐसा उचित नहीं किन्तु किसी ने एक ना सुनी और सोनिया ने जब अपना वीटो पावर लगा दिया तो मनमोहन सिंह ने सरेंडर कर दिया।

गरीबी रेखा के विषय में, मैंने विभिन्न विद्वानों के लेख पढ़े। हरिभूमि 25 मार्च 2012 के पृष्ठ छः पर कुछ अलग-अलग विद्वानों के लेख संग्रहित हैं—तथाकथित विद्वान लेखक निरंकर सिंह, अवधेश कुमार, अलका आर्य, प्रभात कुमार राय आदि के अलग-अलग लेख संग्रहित हैं। सबने मोनटेक सिंह अहलूवालिया और मनमोहन सिंह द्वारा घोषित गरीबी रेखा को 28 रुपये बताने पर या तो इनकी आलोचना की है अथवा मजाक उड़ाया है। विभिन्न टी.वी. चैनलों ने तो कितना नाटक किया वह सबने देखा। किसी ने किसी होटल में जाकर एक कप चाय का दाम 15 रुपये बताया तो किसी ने किसी होटल में जाकर 28 रुपये में आधे पेट भोजन भी ना मिलना बताया। ऐसा लगा जैसे अनेक तथाकथित विद्वान लेखक अथवा टी.वी. चैनल कहीं से पैसे के बल पर संचालित हो रहें हैं, जो तथ्यों को तोड़-मरोड़कर उनके ऐसे भवार्थ प्रस्तुत कर रहें हैं। आज तक किसी लेखक या टी.वी. चैनल ने यह नहीं बताया कि आज से चार-पाँच वर्ष पूर्व गरीबी रेखा बारह रुपये के आसपास थी। किसी मोदी ने कभी यह नहीं बताया कि भाजपा के कार्यकाल में गरीबी रेखा कितने रुपये घोषित थी। प्रश्न उठता है कि इस यथार्थ को छिपाने के पीछे उन तथाकथित विद्वानों का क्या उद्देश्य रहा होगा? योजना आयोग ने जो ऑकडा प्रसारित किया उसके अनुसार गरीबों की संख्या घटी है, इसका भी देश भर के पेशेवर लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया। उन्होंने कभी यह विचार नहीं किया कि मूल्यों को मुद्रास्फीति के साथ जोड़ने के बाद ही कोई ऑकलन हुआ करता है। एक बिना आँख वाला भी देख सकता है, कि पिछले दस वर्षों में जीवन स्तर में सुधार आया है, फिर भी ये आँख वाले विद्वान पता नहीं क्यों जानबूझकर कहते हैं कि गरीबी बढ़ी है, या गरीबों की संख्या बढ़ी है। स्पष्ट दिखता है कि मनमोहन सिंह को एक ओर तो आर्थिक मोर्चे पर असफल करने का प्रयास किया गया तो दूसरी ओर प्रचार के मुद्दे पर भी उन्हें असफल सिद्ध करने में कोई कोर-कसर बाकी नहीं छोड़ी गई। मेरा स्पष्ट संकेत है कि दोनों मोर्चों पर एक साथ प्रयास करने का कार्य किसी साधारण हस्ती के बस की बात नहीं थी और वह हस्ती सोनिया जी के अलावा कोई नहीं।

सुप्रीमकोर्ट ने तो और भी कमाल का काम किया, जब उसने राजनेताओं के समान लोकप्रियता की प्रतियोगिता में स्वयं को शामिल कर लिया। सुप्रीमकोर्ट ने बार बार यह कहकर अपनी विश्वसनीयता घटाई कि गोदामों में सड़ता हुआ अनाज गरीबों में मुफ्त बाँट दिया जाए। अनाज ना सड़े यह सुप्रीमकोर्ट की चिंता का विषय हो सकता है। सरकार सड़ते हुए अनाज को चाहे विदेश भेजे अथवा बाजार में बेच दे अथवा उपभोक्ताओं को सस्ता दे दे अथवा गरीबों को मुफ्त में दे दे, ऐसी सलाह तो संभव है किन्तु यह कैसे संभव है कि बजट से बाहर जाकर अनाज को मुफ्त में दे दिया जाए। आप सोचिए कि सारी आलोचनाओं को झेलते हुए भी मनमोहन सिंह ने सुप्रीमकोर्ट की सलाह ना मानकर जितनी हिम्मत का काम किया, उसके बाद भी क्या वे प्रशंसा के पात्र नहीं हैं। यदि वे चाहते तो मुफ्त में अनाज को बाँटकर प्रशंसा ले लेते, भले ही उसके लिए और नोट छापने पड़ते, भले ही मुद्रास्फीति और बढ़ जाती, भले ही डॉलर के मुकाबले रुपया और

गिर जाता। मैंने अनेक ऐसे मुद्दों में से कुछ आर्थिक मुद्दों ही आपके सामने रखे हैं जो यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं कि मनमाहन सिंह के साथ अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है और मैं ऐसे अन्याय, अत्याचार में पाप का हिस्सेदार नहीं बन सकता।

आप सब पाठक अपनी आलोचनाएं भेज सकते हैं।

1. ओम प्रकाश मंजुल, बरेली उ.प्र.

प्रश्न:—तलवार दम्पति द्वारा अपनी बेटी को अपने ही नौकर के साथ शारीरिक संबंध बनाते देखकर, तलवार दम्पति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सके, और अपनी बेटी तथा नौकर की हत्या कर बैठे। सीबीआई की अदालत में मुकदमा चला और न्यायालय ने दोनों को दोषी पाकर आजीवन कारावास से दण्डित किया।

1: क्या दोनों दया के पात्र नहीं थे?

2: क्या इससे भी अधिक पेशेवर अपराधी खुले नहीं घूम रहें हैं?

3: क्या इस मामले में कठोर दण्ड समर्थक स्वयं के ऐसे ही किसी मामले में शांत रहने की क्षमता रखते हैं ?

4: क्या ऐसे प्रकरण में उत्तेजित होना मानव स्वभाव नहीं है?

5: क्या ऐसे मामलों पर बढ-चढ कर टिप्पणी करने वाले मीडिया कर्मी, न्यायपालिका के लोग अथवा अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं का स्वयं का व्यक्तिगत आचरण बिल्कुल कानून के अनुसार ठीक रहता है ?

आप इस घटना को केन्द्र में रखकर कुछ ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करें।

उत्तर:— यह लगभग निश्चित हो चुका है कि तलवार दम्पति ने ही अपनी पुत्री और नौकर की हत्या की। दोनों अपराधी थे, अपराधियों पर दया करने का अधिकार न्यायालय को नहीं है। किसी भी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति संवैधानिक दायित्व पूरा करने में दया नहीं कर सकता, क्योंकि दया कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत स्तर पर कर सकता है, संवैधानिक स्तर पर नहीं। वैसे भी न्यायाधीश को न्याय करने का अधिकार नहीं है, न्यायाधीश तो कानून के अनुसार ही न्याय कर सकता है, कानून से हटकर नहीं। यदि कोई कानून न्याय के विपरीत भी होगा तो न्यायाधीश कानून के अनुसार ही काम करेगा। मैं इस बात से सहमत हूँ कि किसी भावना या उत्तेजनावश हुए आकस्मिक अपराध तथा सोच समझकर योजनापूर्वक किये गये अपराध के दण्ड में फर्क होना चाहिए, किन्तु यह काम विधायिका का है कि वह कानून बनाते समय इस बात का ध्यान रखे। तलवार दम्पति द्वारा किया गया अपराध न तो माफ करने लायक था जैसा कि आपने कहा है और न इतने कठोर दण्ड देने लायक था, जैसा उन्हें न्यायालय से दिया गया। यदि सारी परिस्थितियों को देखते हुए आठ से दस वर्ष की सजा होती तो पर्याप्त थी।

यह सच है कि तलवार दम्पति के अपराध से भी अधिक गंभीर अपराध करने वाले समाज में खुले घूम रहे हैं। अनेक अपराधों का तो पता ही नहीं चलता। कुछ पुलिस से मिलकर छूट जाते हैं, कुछ न्यायालय तक पहुँचते हैं, वे भी सामान्य गति से आगे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि हजारों में एक मामला ही मीडिया के पंखों पर सवार होकर इतनी तेजी से आगे बढ़ पाता है, जैसे तलवार दम्पति का मामला बढ़ा। इन सब मामलों में न्यायाधीशों को अप्रभावित रहना चाहिए, जो वे नहीं रह पाते और मीडिया में बहुचर्चित मामलों से वे भी प्रभावित होते हैं। यह अनुचित होते हुए भी हम सबकी मजबूरी है कि हम इसमें कुछ नहीं कर पाते। मीडिया तो अपने व्यावसायिक लाभ के लिए अपना न्यूसेन्स वैल्यू बढ़ाता है और इसी के लिए वह हजारों में किसी एक केश को लेकर उसे बहुचर्चित कर देता है। समाज में स्थापित लोग जो स्वयं भी यदा कदा वैसी गलतियाँ करते हैं या कर सकते हैं, यदि उनके साथ भी वैसा ही हो। किन्तु ऐसे अधिकांश लोग अपने आचरण पर पर्दा डाले रखने के लिए, ऐसे बहुचर्चित मामलों को ज्यादा उछालते हैं। उन्हें डर होता है कि सच बात बोल देने से वे स्वयं भी संदेह के घेरे में आ जाएंगे या बहस में पड़ जाएंगे। इसलिए वे ऐसी हवा में बहना अपने लिए लाभदायक समझते हैं। यही कारण है कि सब प्रकार के नेता लोग, सामाजिक कार्यकर्ता या उच्चपदाधिकारी भी मीडिया द्वारा उछाले गए, किसी प्रकरण विशेष के साथ जुड़कर बहती गंगा में हाथ धो लेना चाहते हैं। न्यायाधीश भी ऐसे मामलों में स्वयं को झंझट में नहीं डालना चाहते।

ऐसे मामलों में उत्तेजित होना या नहीं होना अपने व्यक्तिगत स्वभाव पर निर्भर करता है। इसके लिए कोई स्पष्ट नियम नहीं है ना ही यह औसत नागरिक स्वभाव के साथ जोड़ा जा सकता है। आरूषि-हेमराज जैसे संबंधों से उत्तेजित होकर कोई अपने परिवार में वैसा कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। ऐसी घटनाएँ बहुत होती हैं, किन्तु ऐसी हत्याएं बिरले ही होती हैं। हो सकता है इससे भी ज्यादा जघन्य कृत्य कोई कर दे अथवा यह भी संभव है कि कोई चुपचाप शांति से कोई हल निकाल ले। चाहे कुछ भी हो किसी भी परिस्थिति में हो हत्या करने की छूट नहीं दी जा सकती। इतना ही संभव है कि परिस्थिति देखकर हत्या की गंभीरता को कम ज्यादा समझा जा सकता है। मैं सहमत हूँ कि आरूषि-हेमराज की हत्या की गंभीरता को इतनी जटिलता नहीं प्रदान करनी चाहिए थी।

मैं जानता हूँ कि कानून के अनुसार आचरण करने वाले लोग तो अपवाद स्वरूप ही मिलेंगे। अन्यथा कानूनो को तोड़ना या बच निकलना यह या तो हमारा स्वभाव है या मजबूरी। किन्तु ऐसे मामलों में बढ-चढ कर चर्चा करने वालों में अधिकांश लोग वैसी गलतियाँ करते हैं अन्यथा अच्छे लोग बढ-चढ कर ऐसी चर्चाओं में भाग नहीं लेते। ऐसी घटनाओं को आधार बनाकर चर्चाओं को हवा देने वाले अधिकांश लोगों का आंतरिक स्तर संदेहास्पद ही होता है फिर भी हमारे आपके पास ऐसी समस्याओं का कोई ऐसा समाधान

नही दिखता कि हम कुछ कर सकेंगे। आपने बहुत हिम्मत करके ऐसे प्रकरण को उठाने का प्रयास किया इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं।

2. चिन्मय व्यास, मालदेवता देहरादुन, उत्तराखण्ड।

प्रश्न: ज्ञानतत्व 279 में आपने सत्ता के विकेन्द्रीकरण की बात कही है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि हमें सारा ध्यान और शक्ति "सत्ता के विकेन्द्रीकरण" पर लगानी चाहिए। लोकसंसद की बात मनवाना बहुत मुश्किल है, मगर सत्ता के विकेन्द्रीकरण की बात तो अनेक विचारक और अनेक संस्थाएँ कह रही हैं। यह सर्वमान्य कार्यक्रम है इसी पर पूरा जोर लगाना चाहिए तो संसद के मनमाने पन का प्रभाव कम हो जावेगा, संसद की शक्ति ही क्षीण हो जायेगी।

उत्तर— विकेन्द्रीकरण तथा लोकसंसद के आंदोलनों में से कौन सा अधिक कठिन है, इस पर अलग-अलग सोच है। विकेन्द्रीकरण का अर्थ होगा संसद के विधायी तथा कार्यपालिका अधिकारों में कटौती करके, वे अधिकार नीचे की इकाई को देना। गाँधी जी भी ऐसा ही चाहते थे, जयप्रकाश जी भी ऐसा ही चाहते थे, ठाकुर दास बंग भी जीवन भर विकेन्द्रीकरण के लिए लड़ते रहे और अन्ना हजारे भी इसी के लिए लड़ते रहे, किन्तु हम जरा भी सफल नहीं हो सके। इसके विपरीत विधायिका और कार्यपालिका के हमारे हर प्रकार के सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप बढ़ता चला गया। यदि विकेन्द्रीकरण की लड़ाई जरा भी सफल होती दिखती तो मैं लोकसंसद की दिशा में नहीं पडता। मैं समझता हूँ कि लोकसंसद की सफलता विकेन्द्रीकरण की लड़ाई से कुछ आसान भी है और प्रभावी भी। यदि हमने किसी तरह लड़ भिड़ कर विकेन्द्रीकरण में सफलता प्राप्त कर ली और संविधान संशोधन का अधिकार संसद के पास ही रहा तो संसद कभी भी हमारी उस सफलता को जनहित बोलकर वापस कर सकती है। हरियाणा में जनहित में शराब बन्द करायी गई थी और पाँच वर्षों के अंदर ही जनहित में फिर शुरू हो गई। यदि जनहित की परिभाषा तय करने का अधिकार उन्हीं के पास रहेगा तो हमारी लड़ाई का परिणाम कभी भी धोखा दे सकता है, किन्तु यदि संविधान संशोधन का अधिकार संसद के पास से संशोधित हो जाए, तब वे जनहित की परिभाषा अकेले तय नहीं कर पायेंगे। इसलिए ही हमने लोकसंसद के मुद्दे को हाथ में लिया है।

3. सत्यपाल शर्मा, उमरसिया बरेली उ.प्र.।

प्रश्न—पत्रकारिता आज एक विषम दौर से गुजर रही है। पत्रकारिता का स्तर गिर रहा है। विज्ञापनों की चकाचौंध, खबरों को तोड़ मरोड़कर प्रस्तुत करना, पैसे लेकर खबरें छापना, चापलूसी करना आम बात हो गई है। पत्रकारों में संवेदनशीलता, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता घट रही है। पत्रकार राष्ट्र के प्रहरी हैं उन्हें राष्ट्रीय समस्याओं तथा राष्ट्रीय धन के अपव्यय में जिम्मेदारी के साथ जन जागरण करना चाहिए। इस बारे में अपने विचारों से अवगत कराने का कष्ट करें।

उत्तर:— समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कर्तव्यों की अपेक्षा अधिकारों की चिंता अधिक करते हैं। अन्यथा अधिकांश लोग अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्यों की चिंता करते देखे जाते हैं। अधिकार प्राप्त लोग समाज को कर्तव्य करने की प्रेरणा देते हैं और स्वयं कर्तव्य के प्रति जागरूक नहीं होते। ऐसे लोग समाज के अगुवा होते हैं, समाज ऐसे लोगों के पीछे चलता है। अधिकार प्रधान लोग आदर्श को व्यावहारिक बनाकर उनके अनुसार अपनी क्रियाओं को ढाल लेते हैं जबकि शेष समाज से ये लोग व्यावहारिकता को आदर्श के रूप में ढालकर देखना चाहते हैं। आपने पत्रकारिता से अनेक आदर्श अपेक्षाएँ कीं जो उचित नहीं हैं। पत्रकारिता लोकतंत्र का पहला स्तंभ नहीं है, बल्कि चौथा स्तंभ है। आपने चौथे स्तंभ से जो अपेक्षाएँ की हैं उनमें से शेष तीन स्तंभों का आचरण कैसा है इस पर भी विचार करना चाहिए। विधायिका शत-प्रतिशत व्यावसायिक हो गई है, कार्यपालिका भी लगभग विधायिका के समान ही हो रही है तथा न्यायपालिका भी निरंतर उसी ओर अग्रसर है। तब चौथे स्तंभ से आप कैसी उम्मीद रखते हैं ? हमें पत्रकारिता पर विचार करते समय इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि पत्रकारिता किसी तरह से भी सामाजिक दायित्व ना होकर सिर्फ सामाजिक कर्तव्य मात्र है। दायित्व तथा कर्तव्य में अन्तर स्पष्ट है। विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका सामाजिक दायित्व है सामाजिक कर्तव्य मात्र नहीं है, क्योंकि इन तीनों को समाज अपनी ओर से वेतन देकर कार्य के लिए नियुक्त करता है। पत्रकारिता उस प्रकार नहीं है। पत्रकारिता तो एक सीधा-सीधा व्यवसाय है। किसी व्यवसायी अथवा व्यावसायिक कार्य से आप वैसी अपेक्षा नहीं कर सकते जैसी अपने वेतन भोगी से। विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के लोग यदि अपने दायित्व पूरा करने में घपला करते हैं तो वह तीन नम्बर का कार्य माना जाता है, अपराध माना जाता है, समाज विरोधी कार्य माना जाता है। जबकि किसी व्यवसायी द्वारा टैक्स चोरी अथवा किया गया कोई असामाजिक कार्य दो नम्बर का माना जाता है, गैर कानूनी तक ही माना जाता है। पत्रकारिता किसी भी रूप में उन कार्यों में शामिल नहीं है बल्कि पत्रकारिता सिर्फ दूसरे प्रकार के कार्यों में ही शामिल है, जो अनैतिक कार्य तो हो सकता है किन्तु अपराध नहीं, असामाजिक कार्य तो हो सकता है किन्तु समाज विरोधी नहीं, दो नम्बर का कार्य तो हो सकता है किन्तु तीन नम्बर का नहीं। जब समाज के प्रमुख स्तंभ अपने दायित्व से मुँह मोड़ लेते हैं तो पत्रकारिता से ऐसी अपेक्षा करना उचित नहीं दिखता। यह अवश्य है कि यदि पत्रकारिता आगे बढ़कर ईमानदारी से कार्य करना शुरू कर दे तो यह उसकी आदर्श स्थिति मानी जाएगी, किन्तु यदि वह ऐसा ना भी करे तो वह समाज के सामान्य स्तर से इतनी नीचे नहीं मानी जाएगी, जिसके लिए पत्रकारिता की ओर कोई अलग से इशारा किया जाए। मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने कथन पर फिर से विचार करें।

4. योगिन गुर्जर, शोलापुर महाराष्ट्र

प्रश्न:—जब सरकार बनाने के लिए सांसदों या विधायकों के आधे से अधिक सदस्यों की आवश्यकता अनिवार्य है, तो आम चुनावों में आधे से अधिक मत प्राप्त करना अनिवार्य क्यों नहीं? आम-तौर पर देखा जा रहा है कि कुल मतदान का एक तिहाई मत और कभी-कभी तो एक चौथाई मत पाने वाला भी चुनाव जीतकर विधायक या सांसद बन जाता है। जबकि मतदाताओं का तीन चौथाई या उससे भी अधिक उस निर्वाचित जन प्रतिनिधि के विरुद्ध रहता है। यदि ऐसी प्रणाली विकसित हो जाए कि आधे से अधिक वोट प्राप्त करना, अनिवार्य हो जाए तो व्यवस्था बहुत कुछ सुधर सकती है। यदि प्रारंभिक चुनाव में किसी उम्मीदवार को आधे से अधिक वोट नहीं मिलते तो दो निकटमत उम्मीदवारों के बीच दुबारा मतदान कराने की प्रणाली विकसित करनी चाहिए।

उत्तर:—निर्वाचन का महत्व सापेक्ष होता है निरपेक्ष नहीं। महत्व उस कार्य को दिये जाने वाले महत्व से तौला जाता है। यदि किसी ऐसी तिजोरी का पहरेदार रखा जाए, जिस तिजोरी में पच्चीस हजार से ज्यादा रखा ही नहीं जाता, तो उस पर नियुक्त किए जाने वाले पहरेदार की अपेक्षा उस पहरेदार की नियुक्ति में अधिक सतर्कता बरतनी पड़ती है, जिस तिजोरी में करोड़ों रूपया रखा जाता हो, और यदि रखे जाने वाले धन की मात्रा अरबों में होगी तो, पहरेदारों की नियुक्ति में उतनी ही अधिक सतर्कता बरतनी पड़ेगी। कलेक्टर के पद के लिए आईएएस चयन में जितनी सतर्कता अपनायी जाती है, उसी कलेक्टर के अंतर्गत कार्य करने वाले किसी चपरासी की नियुक्ति के लिए उसके दसवें भाग के बराबर भी सतर्कता नहीं अपनाई जाती। जब स्वतंत्रता के बाद के प्रारंभिक वर्षों में चुनाव प्रणाली विकसित हो रही थी, तब ऐसा अंदाज नहीं था कि संसद समाज के सारे कार्य अपने पास समेटकर इतनी महत्वपूर्ण हो जाएगी। उस समय तो सोचा गया था कि समाज के सभी अंग अपना-अपना कार्य करेंगे और उन्हीं अंगों में से एक अंग संसद भी होगी। हम आज भी देखते हैं कि किसी धर्मशाला के चुनाव में वैसी मारा-मारी नहीं होती जैसी सांसद के चुनाव में, क्योंकि धर्मशाला के अध्यक्ष और किसी सांसद के अधिकारों में असीमित अंतर होता है। आज की परिस्थिति के अनुसार तो आपका सुझाव ठीक दिखता है कि सांसद के चुनाव में और अधिक सतर्कता बरती जाए और उसकी प्रणाली में कुछ फेरबदल किया जाए।

किन्तु इस समस्या का एक और समाधान हो सकता है, कि निर्वाचन प्रणाली को अधिक मजबूत करने की अपेक्षा निर्वाचित जन प्रतिनिधि के अधिकार, दायित्व, हस्तक्षेप और अवसर को ही घटा दिया जाए, तो निर्वाचन का महत्व भी अपने आप कम हो जाएगा, और उसमें होने वाली मारा-मारी भी कम हो जाएगी। अर्थात् यदि परिवार, गाँव और जिले को और अधिकार दे दिये जाएं तथा सरकार और सांसद को कुछ ही अधिकारों तक सीमित कर दिये जाएं तो आपके सुझावों का महत्व अपने आप घट जाएगा क्योंकि यदि ऐसा नहीं हुआ तो दूसरा चुनाव भी इतना ही खर्चीला होगा, जो बोज़ बन जाएगा। एक तरीका और भी हो सकता है कि प्राथमिक निर्वाचन के समय सौ-सौ मतदाता एक-एक अन्य व्यक्ति का चयन कर ले और यदि दुबारा मतदान करने की नौबत आए तो ये कुछ हजार लोग ही वोट देकर दूसरा चुनाव करा दें यह भी संभव है। मेरा तो अपना विचार है कि अधिकारों का विकेंद्रीकरण इस समस्या का सर्वश्रेष्ठ समाधान हो सकता है।

5. बाबूराम सैनी— फरीदाबाद हरियाणा।

प्रश्न:— ज्ञानतत्व 273 पढ़ा। जिन राजनैतिक बिन्दुओं, जैसे राइट टू रिकाल, राइट टू रिजेक्ट आदि विषयों पर आप अपनी बैठकों में अनेक बार चर्चाएं किया करते थे, आज उन्हीं विषयों के आधार पर राजनैतिक दल बन गये हैं। लेकिन कृषक और मेहनत करने वालों की स्थिति दयनीय से भी नीचे गिरती चली जा रही है। किसान आत्म हत्या कर रहे हैं। मजदूर नशों में मदहोश होकर मरने को लाचार हैं। न्याय की भाषा अंग्रेजी अनिवार्य है। हिन्दी की माँग करने वाले श्यामरूद्र पाठक एवं गौचर भूमि के आंदोलनकारी गोपाल दास जी भी अस्पतालों और तिहाड जेलों में गिनती में श्वांस ले रहे हैं। बलात्कार जैसे हत्याकाण्ड नित्य ना जाने कितनों के प्राण ले रहे हैं। भविष्य की कल्पना करके प्राण बेचैन है। जीवन का समय कम है, कार्य करने बहुत शेष है, कम समय में देश के लिए अधिक कार्य करने के तरीकों पर सुझाव देने का कष्ट करें। मेरे विचार से अंग्रेजों द्वारा स्थापित काँग्रेस पार्टी का शासन देश हित में नहीं हो सकता। अतः काँग्रेस नामक कलंक को आमूल-चूल शून्यत्व में पहुंचाना देशहित में ही होगा। देश के भविष्य के बारे में अनुभव बॉटें।

उत्तर:— अब तक ना काँग्रेस पार्टी से अधिक नुकसान हो रहा था न ही भाजपा से, परंतु जब से सोनिया गाँधी पुत्र मोह में फँसी हैं तथा संघ परिवार इसका लाभ उठाकर सारी सत्ता अपने पास समेटने लगा है, तब से यह खतरा बहुत अधिक बढ़ गया है। देश के लोगों को सावधान होने की आवश्यकता है।

6. अनिल शर्मा 'अनिल' बिजनौर उ.प्र.।

प्रश्न:— अंक 278-279 में आर्थिक समस्याएँ व समाधान तथा सम-सामायिक विचार पढ़ा। निश्चित रूप से ज्ञानतत्व भरपूर वैचारिक खुराक देता है। पाठकों के प्रश्नों का समुचित उत्तर मिलता है। क्या किसी भी दल ने साम्प्रदायिक द्वेष को बढ़ने से रोकने का ठोस प्रयास किया? आज तक जो प्रयास हुए वे तो मात्र दिखावा व वोट बैंक की राजनीति तक सीमित है, उपाय क्या होगा?

उत्तर:— इस्लाम पूरी दुनिया में एक संगठन है जो शतप्रतिशत साम्प्रदायिक है। इस्लाम को विचारों के आधार पर चुनौती देने की अपेक्षा साम्प्रदायिक आधार पर चुनौती देने का बीड़ा उठाया संघ परिवार ने और इस तरह हिन्दुत्व ही अपने विचारों से हटकर साम्प्रदायिकता

की ओर बढ़ने लगा। साम्प्रदायिक तत्व हमेशा ही सत्ता की साझेदारी की ओर मुँह देखते रहते हैं। स्वतंत्रता के पहले भारत गुलाम था और सत्ता से सहानुभूति रखना संघ की मजबूरी थी। हिन्दु महासभा तो स्वतंत्रता के पूर्व ही सत्ता संघर्ष में शामिल हो गई, किन्तु संघ परिवार ने सत्ता के साथ ताल-मेल करना उचित समझा और यही कारण है कि स्वतंत्रता संघर्ष में संघ परिवार की कोई उल्लेखनीय भूमिका नहीं मिलती बल्कि यदा-कदा अंग्रेजों के साथ अच्छे संबंधों की बात आती है। स्वतंत्रता के बाद कुछ महीने भी नहीं बीते थे कि संघ परिवार पूरी ताकत से सत्ता संघर्ष में कूद पड़ा। चूँकि इस्लाम संगठन के रूप में सत्ता से दूर था, इसलिए संघ परिवार का सीधा टकराव या तो गाँधी विचार धारा से हो अथवा कॉंग्रेस पार्टी से, संघ परिवार ने साम्प्रदायिकता के मुद्दे पर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और धीरे-धीरे कॉंग्रेस पार्टी भी हिन्दू इतर साम्प्रदायिक तत्वों से समझौते करने के लिए मजबूर हो गई। स्वतंत्रता के शीघ्र बाद ही मध्यप्रदेश में नियोगी कमीशन बना जिसने ईसाइयों के विरुद्ध अनेक गंभीर टिप्पणियाँ की। उस समय कॉंग्रेस पार्टी भी मुसलमानों के विषय में लगभग तटस्थ थी किन्तु जैसे-जैसे वोट बैंक में हिन्दुओं का प्रतिशत संघ परिवार की ओर झुकता गया वैसे-वैसे कॉंग्रेस पार्टी भी मुसलमानों की ओर झुकती चली गई और आज यह स्थिति है कि कॉंग्रेस पार्टी लगभग पूरी तरह मुसलमानों को प्रसन्न करने में लगी हुई है। बाद में धीरे-धीरे अनेक दल भी बने किन्तु सभी मुसलमानों की ओर झुकने के लिए मजबूर होते गये। अर्थात् एक भी दल ऐसा नहीं बचा जो आँशिक रूप से भी यथार्थ की बात करे। बिलकुल साफ-साफ मुसलमानों का अत्याचार दिखने के बाद भी सभी दल येन-केन प्रकारेण मुसलमानों के पक्ष में आँख बन्द कर लेते हैं। सच बात तो यह है कि इसका सारा दोष संविधान निर्माताओं की नासमझी पर जाता है जिन्होंने संविधान से समान नागरिक संहिता को तथा, समाज व्यवस्था को भी निकाल दिया, परिवार व्यवस्था और गाँव व्यवस्था को भी बाहर कर दिया और इनकी जगह साम्प्रदायिकता के पोषक द्विअर्थी शब्द धर्म और जाति को डाल दिया। इन सबके समाधान की शुरुवात यहाँ से हो सकती है कि संविधान में समान नागरिक संहिता को डाला जाए तथा संगठनात्मक धर्म या जाति को निकाल दिया जाए। मेरा तो मत है कि भारत में संस्था बनाने की तो छूट हो किन्तु संगठन बनाने की संवैधानिक मान्यता समाप्त कर दी जाए। संभवतः साम्प्रदायिकता पर रोक लगनी शुरू हो जाएगी। किसी भी व्यक्ति को अपना धर्म पालन करने की स्वतंत्रता होगी, धर्म के नाम पर संगठित भी हो सकते हैं, किन्तु धर्म के नाम पर बने संगठन के सहारे किसी प्रकार की अधिकार प्राप्ति की लड़ाई नहीं लड़ सकते। मैं जानता हूँ कि इस्लाम तथा संघ परिवार पूरी तरह इस अवधारणा का विरोध करेंगे और ये दोनों जितना ही विरोध करेंगे उतना ही धर्म निरपेक्ष ताकतें मजबूत होती जाएगी।

7. जितेंद्र निर्मोही : कोटा राजस्थान -9413007724 ।

प्रश्न:- ज्ञानतत्व बराबर मिल रहे हैं, आभारी हूँ। इस युग में स्वस्थ चिंतन भी एक पुनीत कार्य है और उसे बनाये रखना दुष्कर कार्य—जो आप सफलता पूर्वक कर रहे हैं। पत्रिका का निरंतर स्वरूप बनाये रखना भी जीवंतता की निशानी है।

आज कल प्रगतिशीलता के नाम पर जो हो रहा है वह जगजाहिर है। सवर्णों को अछूत तथा निम्न वर्गों के सामंजस्य के साथ आगे बढ़ना आज का सबसे बड़ा कार्य है, क्योंकि अनुसूचित जाति के अलावा जो जन-जाति का तबका उच्च पदों पर आसीन हो गया है वह पूरी तरह सामंती व्यवस्था का अनुसरण करने लगा है। उनमें से जो लोग जमीन से जुड़े हुए हैं वे उनके दोषों को कुशलता से दबा रहे हैं। अनुसूचित जाति के कुछ लोग अनावश्यक अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। उन्हें आज यह याद नहीं कि उच्च वर्ग के उच्च विचार वाले लोग ही प्रारम्भ में इनके बराबर में खाना खाकर और संबंध बनाकर अपनी जात से बेदखल हो गये। ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों को छोड़कर वे उनको भडकाने वाले लोगों के बहकावे में आ जाते हैं। इस तरह आज सामाजिक सौहार्द सबसे बड़ी समस्या है, संवैधानिक समस्या उसके मूल में है, जिसे आप बराबर उठा रहे हैं। आप की विचार क्रांति सराहनीय है।

उत्तर:- किसी भी वर्ग को जब विशेष अधिकार दिये जाते हैं, तब अन्याय तथा अत्याचार बढ़ते हैं। जिस वर्ग को विशेषाधिकार दिये जाते हैं, उस वर्ग के शरीफ लोगों को आँशिक न्याय मिलता है तथा धूर्त लोगों को अन्याय करने के असीमित अवसर प्राप्त हो जाते हैं। ये धूर्त लोग शरीफ लोगों के आँशिक लाभ का उदाहरण दे देकर अपने लाभ के अवसर स्थाई करते जाते हैं। सच्चाई यह है कि यही अनुसूचित जातियों के साथ भी हुआ अनुसूचित जन-जातियों के साथ भी हुआ तथा महिलाओं के साथ भी हो रहा है। स्वतंत्रता के पूर्व सवर्णों को अथवा पुरुषों को जो विशेषाधिकार दिये गये उनका दुष्परिणाम हुआ कि सवर्णों और पुरुषों ने वर्ग के रूप में अनुसूचित जातियों अवर्णों तथा महिलाओं को दबा दिया। व्यक्ति में शराफत या दुष्टता के अलग-अलग गुण होते हैं इनका जाति धर्म या लिंग से कोई संबंध नहीं होता न ही ऐसी कोई सीमाएँ होती हैं। वर्गों में कभी ये गुण समान नहीं होते। न सभी हरिजन आदिवासी शरीफ होते हैं, न सभी दुष्ट। दुष्ट सवर्णों ने वर्ग के आधार पर सबके साथ समान व्यवहार किया जो गलत था। डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने इस विकृति का लाभ उठाकर स्वयं को स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने इस विकृति का स्वतंत्रता के पूर्व लाभ उठाने वालों से समझौता करके अपनी हिस्सेदारी तय कर ली। धूर्त सवर्णों को अम्बेडकर की सलाह में लाभ ही लाभ दिखा और उन्होंने अम्बेडकर की सलाह मानकर यह समझौता कर लिया। परिणाम हुआ कि दो-चार प्रतिशत अवर्ण परिवार सवर्णों के लूट के माल में हिस्सेदारी पा गये और शेष 95 प्रतिशत आदिवासी और हरिजन इस लाभ से आज भी वंचित हैं। हम देख रहे हैं कि ऐसे सभी धूर्त सवर्ण और हिस्सा प्राप्त कर चुके दो-चार प्रतिशत अवर्ण अम्बेडकर जी का इतना गुण-गाण करते हैं जैसे कि वे भगवान ही हों। क्योंकि यदि अम्बेडकर जी नहीं

होते तो धूर्त सवर्णा तथा धूर्त अवर्णों के बीच में यह समझौता नहीं होता, तथा हजारों वर्षों से शोषित आदिवासियों अथवा अवर्णों को सामूहिक लाभ देने का कोई अन्य मार्ग निकलता, जिस मार्ग की खोज अम्बेडकर जी के स्वार्थ ने लम्बे समय के लिए बन्द कर दी। अब समय आ गया है कि वर्गों के नाम पर दिये जाने वाले सब प्रकार के विशेषाधिकार समाप्त करके श्रम को अधिक से अधिक महत्व दिया जाए। मैं जानता हूँ कि श्रम को महत्व देने में न 95 प्रतिशत सवर्ण सहमत होंगे न ही पाँच प्रतिशत अवर्ण जो लूट के माल में हिस्सा लेकर श्रम शोषण में लगे हुए हैं, तथा आदिवासियों, हरिजनों के नाम पर मलाई खा रहें हैं।

8. जगदीश गॉधी : लखनऊ उ.प्र.।

प्रश्न:— ज्ञानतत्व पत्रिका की 16-31 दिसम्बर 2013 की प्रेरणादायी प्रति प्राप्त हुई। इस अंक में आपके द्वारा कई आध्यात्मिक विषयों के साथ ही साथ कई अन्य सारगर्भित विषयों पर भी प्रकाश डाला गया है। जिसके लिए हमारी ओर से ढेर सारी बधाईयाँ।

हमारा मानना है कि कालान्तर में वर्ष 1850 से वर्ष 1950 तक लगभग 100 वर्षों के बीच सारे विश्व में औद्योगिक क्रांति हुई। विश्व के सभी देशों के बीच अपना-अपना सामान अधिक से अधिक बेचकर लाभ कमाने की अत्यधिक होड़ बढ़ने लगी। उस दौड़ में शिक्षा और शिक्षालय भी डूब गये। शिक्षालय केवल कमाई के योग्य व्यक्ति बनाने के टकसाल बन गये। इसके पूर्व शिक्षालयों की चिन्ता होती थी कि बच्चे कैसे अच्छे इंसान बने। यह बात नालन्दा, तक्षशिला, शान्ति निकेतन, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में देखी जाती थी। वर्तमान समय में अच्छे रिजल्ट बनाने की होड़ को कम नहीं किया जा सकता। इस हेतु बालक को अपने सभी विषयों का, संसार का उत्कृष्ट भौतिक ज्ञान मिलना चाहिए, किन्तु इसके साथ ही साथ उसके चरित्र का निर्माण तथा उसके हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम भी उत्पन्न करना होगा तभी हम प्रत्येक बालक को एक अच्छा इंसान भी बना पायेंगे।

उत्तर:— आपने शिक्षा के माध्यम से चरित्र निर्माण की आवश्यकता बताई है। मैं सैकड़ों वर्षों से इस बात को सुनते आ रहा हूँ और आज भी सुन रहा कि शिक्षा से चरित्र बनेगा, किन्तु आज-तक मुझे कहीं भी ऐसा नहीं दिखा कि शिक्षा चरित्र निर्माण का माध्यम बनी हो। मैंने भी इस विषय पर खूब सोचा है और पाया है कि शिक्षा का चरित्र से दूर-दूर तक संबन्ध नहीं है, बल्कि सच बात यह है कि शिक्षा क्षमता का विकास करती है, चरित्र का नहीं। कबीरदास भी चरित्रवान हो सकते हैं और रावण भी चरित्रहीन। यदि कबीरदास शिक्षित होते तो वे अधिक चरित्र की क्षमता का उपयोग कर सकते थे और रावण अशिक्षित होता तो अपनी चरित्रहीनता का इस सीमा तक दुरुपयोग नहीं कर पाता। पूरे भारत में स्वतंत्रता के बाद चरित्र में लगातार गिरावट आयी है और शिक्षा का विस्तार हुआ है। इस बात को हम गलत शिक्षा कहकर तब तक नहीं टाल सकते, जब तक हम अच्छी शिक्षा का विकल्प नहीं दे देते। हमारे आदिवासी क्षेत्रों में 90 प्रतिशत अशिक्षित लोग भी हैं, गरीब भी हैं, शराबी भी हैं किन्तु चरित्र और मानवता के मामलों में पूरे देश में उपर वालों की गिनती में आते हैं। मेरे विचार से सच बात यह है कि चरित्र पर तीन बातों का प्रभाव पड़ता है—1. जन्मपूर्व के संस्कार 2. पारिवारिक वातावरण 3. सामाजिक परिवेश— यदि इन तीनों का प्रभाव विपरीत हुआ तो शिक्षा चरित्र में गिरावट का विस्तार करेगी जैसा कि आज स्पष्ट दिख रहा है।

9. चिन्मय व्यास, मालदेवता देहरादून, उत्तराखण्ड

प्रश्न :— अरविन्द केजरीवाल की आम आदमी पार्टी नये ढंग से काम कर रही है। जनता और जनमत का महत्व बढ़ा रही है। यह देश की राजनीति को नई दिशा देने का प्रयास है। इस पहल को आगे बढ़ाना चाहिए, तथा इसकी समीक्षा करके बताना चाहिए कि इस पहल को ज्यादा कारगर कैसे बनाया जा सकता है। प्रधानमंत्री पद के दो उम्मीदवार मोदी व राहुल गॉधी पद की गरिमा के अनुरूप नहीं बोलते हैं— ज्यादातर एक दूसरे की नुक्ताचीनी करते हैं। उन्हें बताना चाहिए कि यदि वे प्रधानमंत्री बने तो देश की समस्याओं के लिए उनकी क्या पहल होगी? क्या उपाय होंगे? हालत देखते हुए ऐसा लगता है कि अगले आम चुनाव में दिल्ली जैसे नतीजे और हालात केन्द्र में भी हो सकते हैं।

उत्तर:— मैं पिछले दो-तीन वर्षों से लगातार लिखता रहा हूँ कि 2014 में प्रधानमंत्री पद की लड़ाई नरेंद्र मोदी, अरविन्द केजरीवाल तथा नीतिश कुमार के बीच ही होगी तथा होनी भी चाहिए। उस समय अरविन्द केजरीवाल के विषय में ऐसी भविष्यवाणी करने वाला मैं अकेला व्यक्ति था। दिल्ली विधानसभा चुनावों के बाद ऐसी संभावनाएँ टटोलने वाले और भी कई लोग तैयार हो गये हैं। मैं उस समय भी मानता था और आज भी मानता हूँ कि राहुल गॉधी प्रधानमंत्री की इस लड़ाई में दूर-दूर तक नहीं है, और यदि राहुल गॉधी को इस लड़ाई में शामिल करने की भूल की गई तो राहुल गॉधी के साथ-साथ उनको शामिल करने वाले भी डूब जायेंगे। राहुल गॉधी में राजनैतिक सूझबूझ का अभाव है। सामाजिक सूझबूझ सबसे ज्यादा है। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में सामाजिक सूझबूझ तथा राजनीतिक चालाकी के बीच एक संतुलन होना चाहिए, जो राहुल गॉधी में नहीं दिखता। नीतिश कुमार में यह संतुलन दिखता है किन्तु ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी के सामने नीतिश कुमार टिक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी में सामाजिक सूझबूझ की अपेक्षा राजनैतिक चतुराई बहुत अधिक है। जिसका मुकाबला नीतिश कुमार भी नहीं कर पा रहे हैं। अरविन्द केजरीवाल नरेंद्र मोदी का अच्छी तरह मुकाबला कर पायेंगे ऐसा दिखता है।

नरेंद्र मोदी का विस्तार आदर्श स्थिति ना होकर एक मजबूरी है। नरेंद्र मोदी अथवा उनके साथियों में घोषित तानाशाही का मार्ग स्पष्ट दिखता है जो मजबूरी तो हो सकता है किन्तु आदर्श नहीं। अब अरविन्द केजरीवाल के आने के बाद पूरे देश में दो विचार धाराओं के बीच सीधा संघर्ष हो सकता है। जिसमें एक तरफ होंगे तानाशाही समर्थक और दूसरे तरफ होंगे लोकतंत्र समर्थक। जिसका अर्थ हुआ कि नरेंद्र मोदी का उभार लोकतंत्र के नाम पर तानाशाही की ओर झुका हुआ होगा और अरविन्द केजरीवाल का उभार लोकतंत्र के नाम पर लोक-स्वराज की ओर झुका होगा। राहुल गाँधी को इस सीधी लड़ाई में फँसकर या फँसाकर किसी भी तरह लोकतंत्र का नुकसान करना उचित नहीं होगा। पता नहीं सोनिया गाँधी किस तरह धृतराष्ट्र बनीं हुई है अथवा गाँधी। लेकिन सोनिया गाँधी का यह कदम बहुत ही नुकसान दायक है।

10. कुन्दन लाल कुशवाहा खलीलपुर सम्मल उ.प्र.।

ज्ञान तत्व परिवार की सफलता पर हार्दिक बधाई। सफलताओं के लिए परमपिता से शुभकामनाएँ प्रेषित कर रहा हूँ, इन्हें सभी तक पहुंचाने का कष्ट करें—

ज्ञानतत्व लाया सुनो, अजब निराला रंग, जीत गए हैं केजरी, सुनो चुनावी जंग।
नींव पडी सौभाग्य की, इसी जीत के संग, बदलेगा अब शीघ्र ही इस शासन का ढंग।
सुनो उदासी छा गई, बैठे मुँह लटकाए, देख देख अचरज करे और रहे पछिताए।
श्रेय आपको जा रहा, उजड़े चारों खेत, सभी दलों पर आ गई दिशा राहु और केतु।
आशा की किरणें उगी, भारत बने महान, लोकसभा के हेतु भी छिडे यही अभियान।
आज सुनो शासन बना बिनु नकेल का उँट, लोकायुक्त बिठाइये, इसे बाँध दो खूँट।
संविधान की कैद का अब तो काँटो जाल, ले आओ मिलकर सभी अद्भूत एक उछाल।
हम सब मिल करके करें सघन देश प्रचार, जिससे आवे हाथ में संसद का दरबार।
जागो उठो चलते रहो यही समय की माँग, सो मत जाना आप भी पी शराब या भोंग।
शक्ति रहेगी आपके महाकाल के संग, निर्भय रण करते रहो हनुमान बजरंग।
चौकस रहना होश में, घुस ना जाए चोर, जिनके कारण है बना, आज देश कमजोर।
मतदाता का जीतिए मिल करके विश्वास, तो अब निश्चित जानिए विजय आपके पास।
वन्द लेखनी कर रहे अब तो कुन्दन लाल, अपनी अपनी बदलिए अब बैठेगी चाल।
निकल पडो मिलकर सभी लेकर काँति मशाल, ले आओ इस देश में अद्भूत एक उछाल।

उत्तरार्ध

आर्यों की खोज : भाषाशास्त्रीय एवं पुरातात्विक : आचार्य पंकज

सक्तुमिव तितउना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमकत।
अत्रा सखायः सख्यानि जानते भद्रैषां लक्ष्मीर्निहिताधि वाचि।
उत त्वः पश्यन् न ददर्श वाचमुत त्वः शृणवन् न शृणोत्येनाम्।
उतो त्वस्मै तन्वं वि सस्त्रे जायेव पत्य उशती सुवासा ॥

—ऋग्वेद 10.71.2,4 ॥

अथ किमर्थो वर्णानामुपदेशः?.....

इष्टबुद्धयर्थश्च वर्णानामुपदेशः— इष्टाप्वर्णान् भोत्स्यामहे इति।
नहानुपदिश्य वर्णानिष्टा वर्णाः शक्या विज्ञातुम् ॥

—पातंजलमहाभाष्यम् 1.1 ॥

शब्दगत एवं रचनागत न्यूनाधिक सादृश्य के आधार विश्व की प्रायः 3000 भाषाएं अनेक परिवारों और जातियों में बाँटी गई है। यद्यपि इन परिवारों की संख्या और सीमाएं सर्वथा निश्चित नहीं हैं। ऐतिहासिकतया सबसे अलग-थलग अमरीकी महाद्वीपों के प्रचीन निवासियों के अनेक भाषा परिवार हैं। ये लुप्त और मृत प्राय भाषाएं सामान्यतया प्रश्लिष्ट योगात्मक या इनकारपॅरेंटिंग बतायी जाती हैं। एस्किमों एल्गोंकियन अथबास्कन, इरोक्वियन, मुस्कोगियन, सियुअन, पिमन, शोशोनियन, नहुअत्लन, अजटेक आदि अनेक परिवारों में नाना क्षेत्रीय और जातीय भाषाएं संगृहीत हैं। यदि अमरीका में मानव जाति का आव्रजन नवाश्मयुग में लगभग दस हजार ई0पू0 में अलास्का सेतु से माना जाए तो यह स्पष्ट होगा कि वहाँ एस्किमों की प्राचीन भाषाओं में एक सजातीयता की कल्पना पारिवारिक सादृश्य के आधार पर भले ही की जाए, किन्तु उन सादृश्यों के तुलनात्मक अध्ययन से नवाश्मयुगीन मूल भाषाओं का पुररूद्धार संभव नहीं है।

प्रशान्त महासागर की प्रकीर्ण द्वीपावलियों में औस्ट्रानेशियायी या मलैपौलिनेशियायी भाषा परिवार का अनेक शाखाओं में विस्तार है। इस क्षेत्र के उपरी भाग में मलय, जावा बाली, फिलिपाइन, फॉरमूला आदि की पुरानी भाषाएं जिन्हें मलेशियायी या

हिन्देशियायी शाखा का माना गया है। मलैपौलिनेशियायी परिवार की दूसरी शाखा मलैनेशियायी है जो सोलोमन, फिजी द्वीपों में मिलती है। गिलबर्ट मार्शल, केरोलिन आदि द्वीपों में तीसरी शाखा माइक्रोनेशियायी कही गई है। चौथी पौलिनेशियायी शाखा में माओरी एवं समोआ, ताहिती, हवाई, ईस्टर आदि द्वीपों की भाषाएं परिगणित हैं। औस्ट्रानेशियायी भाषाएं अभिश्लिष्ट योगात्मक या एग्लूनेटिव कही गई हैं। पौलिनेशियायी भाषाओं के विभेदन का ऐतिहासिक—पुरातात्विक परिशीलन उसमें संपर्क और स्थानांतरण की भूमिकाएं स्पष्ट करता है।

कुछ लोग मौन—खमेर भाषाओं को औस्ट्रानेशियायी भाषाओं से संबद्ध मानते हैं। मलय, कम्बुज की पुरानी भाषा और अन्नमी इस वर्ग की है। दक्षिणपूर्वी और पूर्वी एशिया से मध्य तक का क्षेत्र हिन्द—चीनी या तिब्बति—चीनी परिवार की भाषाओं का क्षेत्र है। चीनी, तिब्बति, वर्मी और थाई इसके मुख्य विभाग हैं। जापानी, कोरियायी आदि भी इसी क्षेत्र की हैं। ये भाषाएं प्रायः एकाक्षरिक और वियोगात्मक, आइसोलेटिंग हैं।

चीनी तिब्बति के क्षेत्र से सटे मध्य एशियायी क्षेत्र में मंगोल भाषा का सीमित विस्तार है, पर तुर्की या अल्ताई भाषा का विस्तार पश्चिम में एशिया माइनर तक है। तुर्की भी अभिश्लिष्ट योगात्मक या एग्लूनेटिव है।

मध्य और दक्षिण अफ्रीका में बॉटू, बुशमैन, हॉटनेटॉट आदि भाषा—परिवार हैं। उत्तरी अफ्रीका में हामी भाषा—क्षेत्र है जिनमें प्राचीन मिश्री भाषा लुप्त हो चुकी है और समूचे क्षेत्र में इस्लाम के साथ अरबी घर कर चुकी है। पश्चिमी एशिया सामी भाषा—क्षेत्र है, जिसमें पुरानी बाबुली, अक्कदी आदि के अलावा अब अरबी और पुनरुज्जीवित इब्रानी मुख्य हैं।

दक्षिण में हामी—सामी और उत्तर में तुर्की—अल्ताई भाषा क्षेत्रों के बीच में भारोपिय भाषाएं मिलती हैं। मध्य—एशिया में इस समय इनकी एक पतली पट्टी है, जिसमें ईरानी—आर्मान्नी गिनायें जा सकते हैं। पश्चिम की ओर ये भाषाएं फैलकर अधिकांश यूरोप को आच्छादित करती हैं और पूर्व की ओर अधिकांश भारत को। भारत में आर्य भाषाएं मुंडा—द्राविड—तिब्बति—वर्मी भाषा परिवारों से घिरी मिलती हैं। यूरोप में इनके उत्तरी प्रॉत में फिनो उग्रियन या यूरोलिक परिवार की भाषाएं मिलती हैं। यूरोप से भारत तक फैली होने के कारण ही 'आर्यभाषाएं' भारोपीय कहलाती हैं। यूरोप में भाषाएं अनेक परिवारों में बँटी हैं—यूनानी, इतालिक या रोमैस, कैल्टिक, जर्मनिक और बाल्टोस्लाविक, जैसे—भारत में उत्तर—मध्यवर्ती हिन्दी, उत्तर—पूर्वी बंगाली, आसामी आदि भाषाएं, पंजाबी आदि उत्तरी पश्चिमी, मराठी, कोंकनी, सिंहली आदि दक्षिणी आर्य भाषाओं के वर्ग हैं।

विश्व के इन भाषा—परिवारों को देखने से स्पष्ट होता है कि दक्षिणपूर्वी एशिया एवं प्रशान्त महासागरीय क्षेत्र की अश्लिष्ट योगात्मक भाषाओं के वक्ताओं में मूल तत्व प्रोटो—ऑस्ट्रेलाइड या निषादजातीय हैं, जिस पर दक्षिणपूर्वी एशिया में अन्य तत्व आरोपित हैं। पूर्वी और मध्य एशिया की भाषाओं में किरात मंगोलित जाति का प्रधान्य है। मध्य और दक्षिणी अफ्रीका में नेग्रिटो जाति का प्रचार है। उत्तर अफ्रीका और एशिया में जो हामी—सामी भाषाएँ, उनके उपर जो आर्यभाषाएँ और उनके उपर जो तुर्की—अल्ताई भाषाएँ मिलती हैं। उनके वक्ताओं की निश्चित प्रजातीय पहचान नहीं की जा सकती सिवा इसके कि वे मूलतः नेग्रिटो, मंगोलित और प्रोटो—ऑस्ट्रेलाइड नहीं थे, और उनकी उत्पत्ति भी उत्तर अफ्रीका एवं यूरोशिया के, अपेक्षाकृत मध्य भाग में उत्तरी भारत से यूरोप तक विस्तृत क्षेत्र में संभवतः हुई। हामी—सामी, भारोपीय एवं तुर्की—अल्ताई भाषा के व्यवहर्ताओं में निश्चित शारीरिक पहचान अलग—अलग नहीं बताई जा सकती, न वर्तमान युग में आर्य—भाषाभाषियों की ही निश्चित प्रजातीय पहचान बतायी जा सकती है।

नाना भारोपीय भाषाओं की समानताओं की तुलना से एक मूल भारोपीय भाषा की कल्पना की गयी है और उनके आधार पर एक मूल आर्य जाति एवं संस्कृति की कल्पना की गयी है। तुलनीय समानताएँ और व्याकरणिक रचना, मूल धातुएँ और अनेक ऐसे आधारभूत शब्दों में मिलती हैं, जो उधार लिए हुए नहीं हैं। ये समानताएँ ध्वनियों में और उनके नियम कर्मों में मिलती हैं। ये सभी भाषाएँ एकाक्षरिक धातुओं से उपसर्ग एवं परसर्ग लगाकर शब्द निष्पन्न करती हैं और उन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग उनको निश्चित रूपों में रखकर ही होता है। विभिन्न आर्यभाषाओं में धातु, उपसर्ग—परसर्ग, रूप आदि में आश्चर्यजनक एवं नियमानुसारी सादृश्य है। इस सादृश्य को विलिम जोन्स ने पहले देखा, बौप ने समान व्याकरणिक रचना प्रदर्शित की, ग्रिम ने ध्वनि—परिवर्तन के नियम प्रतिपादित किये। अनेक विद्वानों के अनुसंधानों से एक मूल आर्यभाषा की कल्पना की गयी है, जिससे विभिन्न आर्यभाषाओं का विकास निश्चित नियमों के अनुसार बताया जा सके। उदाहरण के लिए संस्कृत 'पितृ' लातिन 'पातेर' अंग्रेजी 'फादर' एक ही मूल शब्द के नियमवर्ती भेद हैं, यह प्रदर्शित किया गया है। इस प्रकार का साम्य अथवा नियत भेद इन भाषाओं में सैकड़ों शब्दों में, मूल धातुओं में प्रत्ययों और विभक्तियों में, कारकों में, लिंग एवं वचन आदि में मिलता है। यह कल्पना की गई है कि एक मूल से विभक्त होकर इन भाषाओं में निश्चित नियमों के अनुसार अपने—अपने भिन्न रूप प्राप्त किये।

मूल भाषा में क्या ध्वनियों थी? क्या धातुएँ और प्रत्यय थे? क्या समान विरासत के रूप में मूल शब्द थे? इन सबके तुलनात्मक अनुमान के आधार पर कल्पना की गई है। पर यह स्मरणीय है कि तुलना पर आधारित रूप तुलना के तत्वों को ही प्रस्तुत करते हैं, मूलभाषा के वास्तविक शब्दों को नहीं, वे तुलना सूत्र हैं, यथार्थ शब्द नहीं। एक समय यह माना जाता था कि संस्कृत मूलभाषा

के संनिकृष्ट है, पर अब यह नही माना जाता। संस्कृत मे मूल व्यंजनों का संरक्षण अधिक हुआ, यूनानी मे मूल स्वरों का, यह कल्पना अब प्रचलित है। मूलभाषा की ध्वनियों निम्न प्रकार की मानी जाती है:-

(अ) स्वर—व्यवस्था —

मूल — अ, ऐ, ई, औ, उँ, ('श्वा' अव्यक्तवत स्वर)

दीर्घ — आ, ए, ई, ओ, ऊ

संयुक्त स्वर — ह्रस्व—

अँइ, ऐँइ, ओँइ,
अँउ, ऐँउ, ओँइ

दीर्घ — आइ, एइ, ओइ,

आउ, एउ, ओउ

(ब) व्यंजन —व्यवस्था —

स्पर्श— शुद्ध कण्ठ्य

कवर्ग — क्, ख्, ग्, घ्, (वेलर)

क्य्, ख्य्, ग्य्, घ्य्, (कंठ—तालव्य)

क्व्, ख्व्, ग्व्, घ्व् (कंठोष्ठ्य)

तवर्ग — त, थ, द,

पवर्ग — प, फ, ब, भ

उष्म — स, ज,

अनुनासिक — म, न

अन्तस्थ — य, व, र, ल

इस प्रकार की मूल वर्णमाला आधुनिक भाषातत्त्वविदों का अविष्कार है। वह किसी भी वर्तमान या अतीत की भारोपीय भाषा से सर्वथा अभिन्न नहीं है और उसकी सत्यता संभावना मात्र तक सीमित है। संस्कृत में 'ए' और 'ओ' संयुक्त और दीर्घ स्वर हैं। ह्रस्व 'ऐ' और 'औ' प्राकृत और आधुनिक भाषाओं में मिलते हैं। इसी प्रकार अइ, एउ, ओइ, आदि संयुक्त स्वर भी संस्कृत में न मिलकर उससे निकली भाषाओं में मिलते हैं। ऐसी स्थिति में यूनानी आदि भाषाओं में नाना संयुक्त स्वर देखकर उन्हें मूलभाषा का संरक्षण न मानकर परवर्ती विकृतियाँ मानना क्या ठीक नहीं होगा। ऐतिहासिक दृष्टि से भी यूनानी आदि भाषाओं के उपलब्ध रूप प्राकृत भाषाओं के उदय के समकालीन ही माने जा सकते हैं। मध्य हिन्द-ईरानी भाषागत वैशिष्ट्य को मूल भारोपीय मानने के लिए संस्कृत और यूनानी को मूलभाषा से समान दूरी पर समान रूप से प्रामाणिक मानने का आग्रह है। दूसरी ओर घ ध भ जैसी सघोष महाप्राण ध्वनियों सिर्फ संस्कृत और तन्मूलक भारतीय भाषाओं में मिलती हैं। जिससे संस्कृत की मूलभूमि भारत ही सिद्ध होती है।

संस्कृत को ही मूलभाषा माना जाए, यह आग्रह यहाँ अभीष्ट नहीं है। वस्तुतः किसी भाषा का मानक रूप शिक्षा, अनुशासन और लेखन से ही स्थिर होता है। अन्यथा वह अनेक भिन्न बोलियों के रूप में मिलती है। जिनमें किसी को भी दूसरी से स्वतः अधिक प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। विभिन्न बोलियों एक मूल भाषा के विकार नहीं हैं बल्कि एक मानक भाषा किसी एक बोली का सम्यक व्याकृत एवं आधिकारिकतया शिष्ट-सम्मत रूप है। एक मूल भारोपीय भाषा की कष्ट कल्पना से बेहतर यह कल्पना है कि वह नाना न्यूनाधिक दूरियों के प्रदेशों की अन्योन्य संबद्ध बोलियों की समाहार थी। इन बोलियों से विकसित भाषाओं का प्राचीन इतिहास अज्ञात अथवा अत्यन्त अधूरे रूप से ही ज्ञात है। उनका व्यापकतम विभाजन शतम् और केन्तुम् परिवारों में किया गया है। पर उनका भी न तो क्षेत्रीय विभाजन निरपवाद है, न विभाजन काल ही ज्ञात है। मूल भारोपीय की कण्ठीय ध्वनियों केन्तुम् परिवार में कण्ठीय ध्वनियों के रूप में शेष रहती है जबकि शतम् परिवार में वह उष्म ध्वनियों बन जाती है। मूल भारोपीय शब्द था कमतौम् जिसका केन्तुम् लातिन में और शतम् संस्कृत में बन जाता है। शतम् परिवार में हिन्दी-ईरानी, बाल्टोस्लाविक, आर्मीनी और अल्बानी संग्राह्य है। केन्तुम् परिवार में यूनानी, इतालिक, केल्टिक, जर्मनिक, हिटाइट और तोखारी गिनी जाती है। केन्तुम् परिवार में स्पर्श ध्वनियों के परिवर्तन का एक प्रसिद्ध नियम ग्रिम द्वारा प्रतिपादित है। इस प्रकार के नियम भाषागत ध्वनि-परिवर्तन को व्यवस्थित रूप अवश्य देते हैं किन्तु उनका व्यापार निरपेक्ष नहीं माना जा सकता। भाषा-नियमों का सर्वोत्कृष्ट प्रतिमान पाणिनीय व्याकरण है जिससे आधुनिक तुलनात्मक भाषा विज्ञान को प्रेरणा मिली। पर उसमें भी वस्तुगत तथा बौद्धिक कल्पनाएँ मिली-जुली हैं। व्याकरण के नियम लोक-सिद्ध एवं शिष्ट सम्मत रूढ़ियों के ज्ञापक हैं न कि कारक, न वे स्वतंत्र कार्य-कारण नियमों के प्रतिरूप हैं। उच्चारण की प्रवृत्तियाँ प्रादेशिक रूप से पायी जाती हैं पर उन्हें शाश्वत या स्थिर नहीं माना जा सकता। उदाहरण के लिए भारत में टवर्ग का उच्चारण और स्वराघात का अभाव प्रचुरता से मिलता है, योरोप में इसका उल्टा है। पर भारत में ही संयुक्त स्वरों एवं व्यंजनों के उच्चारण में अन्तर आ गया है। इन प्रवृत्तियों में कितना हाथ आनुवंशिक जातियों का है, कितना समुदायों के अन्योन्य सम्पर्क का, कितना आगन्तुक कारणों से परिवर्तित-संरक्षित सामाजिक परम्परा का, यह निश्चित करना कठिन है, विशेषतया प्रागैतिहासिक युग की अविदित भाषाओं के लिए जिनके आनुमानिक साक्ष्य बहुत बाद के हैं।

भारोपीय परिवार में संस्कृत ही एकमात्र भाषा है जिसका रूप और इतिहास कम से कम 3500 वर्षों से अधिक का ज्ञात है। उसे अवरकालिक भाषाओं के समक्ष मानकर सबके अधिकतम समान मान (हाइयेस्ट कॉमन फ़ैक्टर) के रूप में एक मूलभाषा की कल्पना असंदिग्ध नहीं कही जा सकती। उस भाषा के वक्ताओं के समुदाय के रूप में आर्यजाति की कल्पना और संदिग्ध है। आर्यभाषा के 'सजातीय' शब्दों से उस जाति की संस्कृति की कल्पना प्रायः पूर्व सिद्ध कल्पनाओं को ही पुष्ट करती है। एक मत से मूलगामी शब्दों में कुछ संस्कृत के इन शब्दों के मूल

थे— शर्धः, गो, अवि, अज, शूकर, श्वन, अश्व, वृक, ऋक्ष, सारस, हंस, मक्षिका, मधु, भूर्ज, ओक, बीच, विलों (वेतस्?) यव, अयस्। सिंह, व्याग्र, हस्तिन आदि शब्द भारोपीय मूल के नहीं हैं। इससे सूचित होता है कि भारोपीय जाति मुख्यतया नवाश्मयुगीन आरंभिक कृषि के साथ पशुधन पर निर्भर, समुद्र से दूर पहाड़ों के निकट और बीच के क्षेत्र में अवस्थित थी। 'बीच' से क्या आर्य परिचित थे? क्या 'भगोस' शब्द इस अर्थ में मूलभाषा में था? क्या मूलभाषा में जलाशयवाची शब्द समुद्रवाची था? क्या कोई धातुवाची शब्द मूल आर्यभाषा में था? क्या अयस् शब्द मूलतः भारोपीय एवं धातुवाची था?

इन प्रश्नों पर निश्चय का समुचित आधार नहीं मिलता क्योंकि विभिन्न भाषाओं में एक ही क्षेत्र अथवा अवस्था सूचित नहीं है। वैदिक संस्कृत में 'बीच' या 'एल्म' का कोई चिह्न नहीं है, समुद्रवाची शब्द स्पष्ट है, अयस् धातुवाची है।

योरोपीय पुरातत्वविदों ने पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर आर्यों को खोजने में प्रयास किया है। लिथुवानियन पुरातत्वविद मार्या गिम्बुतास ने दक्षिण रूस की कुर्गन संस्कृति को माल आर्य संस्कृति बताया है और उसका विस्तार छठी से चतुर्थ सहस्राब्दी ई०पू० में दक्षिणीपूर्वी योरोप में खोजा है। किन्तु किसी पुरातात्विक संस्कृति को आर्य किस आधार पर कहा जा सकता है, यह स्पष्ट नहीं है। भारत और उसके पास भी योरोप की तरह एकाधिक प्राचीन नवाश्मयुगीन बस्तियाँ मिलती हैं जो संभवतः आर्य हो सकती हैं। वंशु के सन्निकट अक्कुप्रक में ई०पू० 8000 के लगभग नवाश्मयुगीन बस्ती में पालतू पशुओं के चिह्नों में घोड़े का भी पता चलता है। ई०पू० 8000 से ई०पू० 2000 के बीच वहाँ मृदभांडरहित, मृदभांडीय और ताम्रशमीय अवस्थाएँ मिलती हैं, जो रूसी मध्य एशियायी बस्तियों से तुलनीय हैं। ऐसा ही विकास बलूचिस्तान और दक्षिणी अफगानिस्तान में मेहरगढ़ और मुंडिकाक में ई०पू० 6000 से ई०पू० 3000 के बीच उपलब्ध होता है। इस विकास में तुर्कमेनिस्तानी या मध्य एशियायी सम्पर्क की भूमिका का प्राधान्य नहीं प्रतीत होता। न उसमें आर्यों की पहचान निश्चित की जा सकती है। जैसे—योरोप में पाषाण—युग से सभ्यता के युग तक अविच्छिन्न विकास से वहाँ आर्यों के मूल निवास की कल्पना की गयी है, वैसे ही भारत में भी संभव है। इस सम्पूर्ण विकास में भारत में एशियायी सम्पर्क वैसे ही निश्चित है, जैसे योरोप में। नवाश्मयुगीन कौंगडा घाटी की संस्कृति का रूसी—मध्य एशियायी गिस्सार संस्कृति पर प्रभाव बताया गया है। हडप्पा संस्कृति का तुर्कमेनिस्तान तक प्रसार पता चलता है।

गन्धार शवाधान संस्कृति ई०पू० 1400 से ई०पू० 900 तक प्रमाणित है। उसमें तौबें का और बाद में लोहे का उपयोग मिलता है। तीसरे स्तर में पालतू घोड़े का पता चलता है, मृतकों का शवाधान मिलता है। इन लक्षणों से इस संस्कृति को आर्य कहा गया है। प्रथम और तृतीय स्तर के नृतवीय भेद और तीसरे में पिछली बस्ती का विध्वंस इस बात का संकेत माना गया है कि तृतीय स्तरीय लोग एक भिन्न तरंग के रूप में आये थे। पर आर्यों के भारत में आक्रमण के लिए इस संस्कृति की तिथियाँ बहुत बाद की हैं। ऐसे ही सेमिटरी 'एच' की आर्यों से पहचान भी अविश्वस्य प्रतीत होती है क्योंकि उस संस्कृति का विस्तार बहुत सीमित है। दक्षिण, मध्य और उत्तर भारत में दूसरी सहस्राब्दी में मिलने वाली ताम्रशमयुगीन संस्कृतियों को आर्य मानने के लिए कोई निश्चयात्मक प्रमाण नहीं है। यही स्थिति चित्रित—धूसर भांड संस्कृति की है।

पश्चिमी एशिया में हिसार 2—3, गियान—2, अनाउ 2—3, शाह टीपे—2 और तुरंग—टीपे में आक्रमण और प्रवजन की उथल—पुथल ई०पू० तीसरी—दूसरी सहस्राब्दी में प्रमाणित होती है। शाह टीपे में पालतू घोड़े के चिह्न भी मिलते हैं। इस युग में एशिया माइनर में अभिलेखों से आर्यों की उपस्थिति सिद्ध होती है, किन्तु जहाँ कहीं घुमंतु जातियों या आक्रमण को देखने से आर्यों की उपस्थिति सिद्ध नहीं होती।

वस्तुतः आर्यों की पहचान मात्र भाषा है, भाषारहित भौतिक संस्कृति से उनकी पहचान नहीं हो सकती है। वरना नवाश्मयुग से लौहयुग तक उनके चिह्न बहुत स्थानों पर माने जा सकते हैं। मूल आर्यजाति, मूल आर्य निवास, मूल आर्य संस्कृति और आर्यों का प्रागितिहास, इनकी खोज वस्तुतः उपलब्ध भाषात्मक प्रमाण के अभाव में शशश्रृंग की खोज बन जाती है। तुलनात्मक भाषाशास्त्र भारोपीय भाषाओं की समानताओं और संबन्धों पर प्रकाश डालता है, पर वह उनके लुप्त प्रागितिहास का पुनरुद्धार नहीं कर सकता। ऐसे ही अभिलेख रहित प्रागितिहासिक पुरातत्व भौतिक सभ्यता का सामान्य विकास बता सकता है, पर किसी विशिष्ट समाज अथवा संस्कृति की अपनी पहचान नहीं बता सकता।

विशुद्ध भाषाशास्त्रीय अभिकल्पना अथवा विशुद्ध पुरातात्विक अनुमानों से भारोपीय इतिहास का विश्वास योग्य पता नहीं चल सकता। अभिलेखिक एवं साहित्यिक साक्ष्य के मिलने पर भाषाशास्त्र एवं पुरात्व दोनों ही ज्ञान के साधन बन जाते हैं। दूसरी सहस्राब्दी ई०पू० के पूर्वार्ध में एशिया माइनर और सीरिया में भारोपीय भाषाएँ बोलने वालों के शासन के प्रमाण मिलते हैं। तेल—अल—अर्मना और बोगजकुई के मिस्त्री और खत्ती अभिलेखागारों में ये प्रमाण सुरक्षित हैं। खत्ती भाषाभषी जिस जनता पर शासन करते थे, उसकी भाषा अन्य थी। स्वयं खत्तियों की भाषा अपनी व्याकरणिक संरचना और कुछ महत्वपूर्ण शब्दों में स्पष्टतः भारोपीय है पर उसकी शब्द राशि में विजातीय शब्दों की भरमार है, विशेषतया सुमेरियायी—असीरियायी आइडियोग्राम्स का। खत्ती जाति एशिया माइनर में कहाँ से आयी और उसका मूल भारोपीय से ठीक संबन्ध क्या था, यह संदिग्ध है। खत्ती केन्तुम् परिवार में रखी जाती है पर वह भारोपीय की दुहिता न होकर स्वसा हो सकती है।

दूसरी ओर तेल-अल-अमर्ना के पत्रों से यह स्पष्ट है कि ई0पू0 15वीं सदी में सीरिया में भारोपीयभाषी शासक थे। उनके नाम संस्कृत के अत्यन्त निकट थे-स्वरदात, अर्तमन्यु, सुबन्दु। मितन्नी और खर्री जनों के शास्त्रों में भी ऐसे नाम मिलते हैं-अर्ततम, अर्तस्वर। सीरिया के इन राज्यों में योद्धा वर्ग की आख्या मर्यन्नु (संस्कृत मर्य) मिलती है। यही नहीं, बोगजकुई के अभिलेखों में खत्ती सम्राट, शुब्बिलुल्यूमा और मितन्नी शासक मत्तिवाज के बीच एक संधि में जिन अनेक देवताओं की शपथ उठाई गयी है उनमें कुछ स्पष्ट रूप से भारतीय देवताओं के नाम हैं-मित्र, वरुण, इन्द्र और नासत्या। खत्ती में द्विवचन न होने के कारण 'मित्रावरुणा' इस देवता-द्वन्द्व को बताने के लिए पृथक-पृथक बहुवचन का प्रयोग किया गया है, यही प्रकार 'नासत्या' के लिए अपनाया गया है। इन्द्र और वरुण दोनों ही वैदिक देवता हैं। इसके अतिरिक्त एक किककुलि नाम के मितन्नी का लिखा हुआ आजि-धावन का प्रकरण भी वहाँ मिलता है। जिसमें एक-वर्तन, तेर-वर्तन पंज-वर्तन, सत्त-वर्तन, ना-वर्तन, आदि शब्द मिलते हैं, जो स्पष्ट ही संस्कृत के हैं। अवेस्ता में एक के लिए ऐव मिलता है। ऐसे ही 'सत्त' प्राकृत रूप से अभिन्न है और अवेस्ता के हप्त (परवर्ती हप्त) से दूर। इन सभी साक्ष्यों से सिद्ध होता है कि ई0पू0 1500 के आस-पास वैदिक संस्कृतभाषी भारतीय शासक, योद्धा और व्यापारी सीरिया में बसे हुए थे। ये भारत से पश्चिम की ओर गये हुए थे। यही मानना समुचित प्रतीत होता है, जैसा कि एदुआर्द मायर ने भी 1928 ई0 में माना था। 1977 ई0 में बरो का कथन है कि इन सीरियायी आर्यों की तीन प्रकार से पहचान संभव है-वे ईरानी हो सकते हैं, भारतीय हो सकते हैं, इन दोनों के पूर्वज हो सकते हैं। इन तीनों विकल्पों में उन्हें भारतीय मानना ही इस समय सर्वाधिक सम्मत है। पर वे भारत से गया हुआ न मानकर वहाँ से गया हुआ मानते हैं जहाँ से वे भारत आये थे।

इन आभिलेखिक साक्ष्यों से पूर्व में भी कस्सी राजवंश के शासकों और देवताओं के नामों में वैदिक नाम मिलते हैं। जैसे-सूर्यस्, मरुतस्, अबिरत्तस्। कस्सियों का शासन लगभग 1750 ई0पू0 से प्रारम्भ होता है। ईराक की मित्तनी संस्कृति में मयूर का अभिप्राय मिलता है। मित्तनी सिलिण्डर सीलों में मयूर चित्रित मिलता है। यह स्मरणीय है कि हडप्पा संस्कृति में इस प्रकार का अभिप्राय सर्वप्रथम उपलब्ध होता है। हडप्पा संस्कृति का पश्चिमी एशिया से व्यापारिक सम्पर्क ई0पू0 तीसरी सहस्राब्दी से था। ई0पू0 दूसरी सहस्राब्दी में भारत और पश्चिमी एशिया में यह सम्पर्क एक दूसरे रूप में मिलता है, जिसमें आर्य भाषाभाषियों की भूमिका स्पष्ट नहीं है।

एक प्रचलित मत के अनुसार आर्य एक लडाकू और असभ्य जाति थी। जिसके समुदायों ने अनेकत्र स्थानीय जनता को पराजित कर अपना शासन और भाषा उन पर आरोपित की किन्तु उन्होंने स्वयं उन्नततर विजित जाति की सभ्यता को क्रमशः अपना लिया। खत्तियों का इतिहास इसका एक दृष्टान्त है। मित्तनी और कस्सी इतिहास में भी इसकी झलक है। यूनानी इतिहास इसका महत्वपूर्ण निर्देशन है। मिनोआयी-संस्कृति पर अधिकार स्थापित कर यूनानी संस्कृति उसकी ऋणी न सिर्फ भौतिक-सामाजिक जीवन, धर्म और कला में बनी बल्कि स्वयं उसकी भाषा में बहुत से शब्द बाहरी मूल के भर गये।

एक मत के अनुसार भारत में भी ऐसा ही हुआ। असभ्य पर लडाकू आर्य जाति ने सिन्धु सभ्यता का विध्वंस किया पर उसके अनेक तत्वों को क्रमशः अपना लिया। यदि सिन्धु-सभ्यता सर्वथा आर्यतरीय है तो इसमें मौलिक सत्य स्वीकारना होगा। यद्यपि आर्यों को विध्वंसक नहीं माना जा सकता तो भी वैदिक संस्कृति को विशुद्ध आर्य न मानकर एक मिली-जुली संस्कृति मानना ही ठीक रहेगा। वेद भी किसी लडाकू बर्बर जाति का प्रतिनिधित्व नहीं करते बल्कि एक जाति-निरपेक्ष विश्ववारा संस्कृति व्यक्त करते हैं। आर्य और द्राविड आदि के भेद और संघर्ष के स्थान पर उनके शान्तिपूर्ण सम्बन्ध और समन्वय को ही इस संस्कृति का मूल मानना होगा। वस्तुतः संस्कृति और सभ्यता के इतिहास में आधुनिक प्रजातीयतावाद और उस पर ही निर्भर संकीर्ण राष्ट्रीयतावाद का कोई स्थान नहीं है। ये विश्ववारा संस्कृति की अन्तर्भूत प्रतनु धाराएँ हैं।

पिछले विवरण से यह स्पष्ट होगा कि भारत में आर्य और आर्यतरीय भाषा परिवारों का सर्वथा और विरोधात्मक पार्थक्य नहीं रहा है। इन सभी परिवारों के बीच में और उनके अन्दर आदान-प्रदान चलता रहा है। जो कि साँस्कृतिक समन्वय की परम्पराओं से जुड़ा रहा है। आर्य-अनार्य, आर्य-द्राविड आदि प्रभेदों को उजागर करने के पीछे वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठता राजनैतिक उद्देश्यों से रंजित हुई है। जैसे भारत एक साँस्कृतिक इकाई है। ऐसे ही वह एक समन्वित भाषाई क्षेत्र है। इस स्थिति का आरम्भ प्रागैतिहासिक है और पूर्व वैदिक युग को इसके सहारे ही समझना चाहिए। मूल आर्य भाषा के स्वरूप, प्रसार और पारस्परिक आदान-प्रदान के विषय में नवीन भाषाशास्त्रीय अनुसंधान इसी दिशा में संकेत करता है। द्राविड भाषा के सम्बन्ध में भी अब पिछली मान्यताओं से हटकर भी उहापोह जारी है।